खण्ड–5, अंक–1, वर्ष–2017, मु0पृ0 187–188, D.O.I. : 10.22445/avsp.v5i01.9880 वैज्ञानिक लेख

पृथ्वी रक्षा

रश्मि सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
प्रताप बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़ सिटी–232002, उ0प्र0, भारत
rashmi6619@gmail.com

प्राप्त तिथि–30.06.2017, स्वीकृत तिथि–08.09.2017

सार– विकसित देश बनने की प्रतिस्पर्धा में, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक विदोहन तथा अनुचित विदोहन कर रहे हैं। हम पर्यावरण की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं और परिणाम स्वरूप हमें ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, संसाधनों का क्षरण आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि हम इन समस्याओं की ओर ध्यान दें, इन्हें नियन्त्रित करें अन्यथा हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अन्तर पीढ़ी समानता और अन्तः पीढ़ी समानता सतत् विकास के लिए मुख्य बिन्दु हैं। सतत् विकास के लिए पर्यावरण की रक्षा आवश्यक है। इसी प्रकार पर्यावरण रक्षा के लिए सतत् विकास नीति अपनाना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें सत्र में, संपोषणीय विकास उददेश्यों को अपनाया। दिसम्बर 2015 में, पेरिस में एक ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन करार हुआ। पेरिस करार, यूएनएफसीसीसी के तहत एक करार है। यह दुनिया का पहला व्यापक जलवायु करार है। भारत ने अपना आईएनडीसी अक्टूबर 2015 में प्रस्तुत किया। इस सुन्दर पृथ्वी को बचाने हेतु ये महत्वपूर्ण कदम है।

बीज शब्द– पर्यावरण, पेरिस समझौता, सम्पोषणीय विकास।

Earth protection

Rashmi Singh
Associate Professor, Department of Economics
Pratap Bahadur Post Graduate College, Pratapgarh City-232002, U.P., India
rashmi6619@gmail.com

Abstract- In the race to become a developed country, we are over utilizing as well as exploiting our natural resources, as a result we are facing problems like global warming, pollution, depletion of resources and so on. Now the time has come that we pay attention to these problems and protect life on earth, otherwise we will suffer serious consequences. Inter-generational equity and intra-generational equity are key aspects for sustainable development. For sustainable development, protection of environment is essential. Likewise, for protection of environment the adoption of policy of sustainable development is essential. At the 70th United Nations General Assembly session, sustainable development goals were adopted. In December 2015, at Paris there was a historical climate change agreement. Paris Agreement is an agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change [UNFCCC]. The Paris deal is the world's first comprehensive climate agreement. India presented its Intended Nationally Determined Contributions [INDC] in October 2015. These are important steps towards protection of our beautiful earth.

Key words- Global warming, sustainable development, UNFCC.

1. **प्रस्तावना–** वर्तमान समय में विकास की दौड़ में पर्यावरण की उपेक्षा हुई है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समस्याओं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण आदि का सामना विश्व को करना पड़ रहा है। विकास की इस दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का भी अति विदोहन हुआ है जिसके फलस्वरूप बहुत से संसाधन लुप्त होने की कगार पर हैं। यदि पृथ्वी पर जन–जीवन को बचाना है तो ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण आदि को नियंत्रित करना जरूरी है और साथ ही सतत् विकास नीति भी अपनाना अत्यन्त आवश्यक है। वर्ष 2015 में दो अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो सम्भवतः विश्व को कम कार्बन वाले, समुत्थानशील और सतत् विकास के भविष्य की ओर ले जाएंगी। सितम्बर 2015 में संपोषणीय विकास लक्ष्यों का अपनाया जाना तथा दिसम्बर 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन करार। भारत इनका हिस्सा है।[1]

2. **भूमण्डलीय ऊष्मीकरण(ग्लोबल वार्मिंग)**– पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के समीप वायुमण्डल तथा क्षोभमण्डल में औसत तापमान वृद्धि है जिसके कारण वैश्विक जलवायु में परिवर्तन

हो सकते है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वर्ष 2015 सबसे तप्त वर्ष था। वर्ष 2015 में पूर्व औद्यौगिक युग से 10 सेटीग्रेट तापमान अधिक था और इसका मुख्य कारण एल–नीनो और ग्रीनहाउस गैसें थी। ऊर्जा क्षेत्र ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान करते हैं और जिसमें ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाई ऑक्साइड का सबसे बड़ा हिस्सा है। विभिन्न देशों में उत्सर्जन भिन्न–भिन्न स्तर पर है। नासा (एनएएसए) तथा एनओएए के अनुसार, वर्ष 2015 को पीछे छोड़ते हुए, वर्ष 2016 अब तक का दर्ज उत्तप्त वर्ष था।[2,3]

3. **उत्सर्जन–** अंतर्राष्ट्रीय उर्जा एजेंसी रिपोर्ट वर्ष 2015 के अनुसार कार्बन डाई ऑक्साइड की सघनता 1800 के मध्य में जितनी थी उससे 40 प्रतिशत अधिक है। यदि 1970–2014 से ऐतिहासिक कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को देखा जाए तो भारत 39.0 जीटी के साथ यूएसए, ईयू, और चीन जैसे शीर्ष उत्सर्जक देशों से बहुत पीछे है[यूएसए: 232. 0जीटी]। सम्पूर्ण उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दोनों ही अर्थों में भारत तीन प्रमुख कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जक देशों(यूएसए, ईयू और चीन) से बहुत पीछे है।

4. **पेरिस समझौता**– जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र ढाँचा अभिसमय में पक्षकारों(सीओपी 21) का 21वां सम्मेलन दिसम्बर 2015 के प्रथम सप्ताह में पेरिस में सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ, इसके बाद जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में वर्ष 2020 के बाद के कार्यों के लिए पेरिस समझौता अपनाया गया। यह सभी देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध कार्य करने हेतु एक ढाँचा प्रदान करता है। पेरिस समझौता जलवायु, न्याय और संपोषणीय जीवन शैली जैसी अवधारणाओं पर बल देता है। इसमें 139 पैरा और 29 अनुच्छेद है। इस करार का एक मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित रखना है। भारत ने 2 अक्टूबर 2015 को यूएनएफसीसीसी को अपनी आईएनडीसी प्रस्तुत कर दी थी। आईएनडीसी सरकार की एक विस्तृत योजना है जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में जानकारी यूएनएफसीसीसी को प्रदान की जाती है।[4]

5. **सत्रहवीं संयुक्त राष्ट्र महासभा**– सतत् विकास प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए, वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करता है। सतत् विकास की वह अवधारणा है जिसमें विकास की नीतियाँ बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मानव की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वरन् उन्नत काल मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा(यूएनजीए) ने अपने सत्रहवें सत्र, सितम्बर 2015, में 17 संपोषणीय विकास उददेश्यों(एसडीजी) और 169 लक्ष्यों की घोषणा की, जो अगले 15 वर्षों में कार्य को प्रोत्साहित करेगा। इसमें गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना, स्वास्थ और शिक्षा में सुधार, शहरों को अधिक संपोषणी बनाना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, जंगलों की रक्षा करना आदि शामिल है।[5]

इसका लक्ष्य संपोषणीय विकास की ओर अग्रसर होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और राष्ट्रीय सरकारों का मार्ग दर्शन करनाहै। एसडीजी का बहुत व्यापक लक्ष्य है और 169 लक्ष्यों में से प्रत्येक का संकेतक पाना भारत के लिए चुनौती पूर्ण रहेगा। एसडीसी लक्ष्यों को हासिल करने में वित्त पोषण और पर्याप्त निगरानी तंत्र जैसी मुख्य चुनौती पेश आएगी फिर भी भारत को प्रयास करना आवश्यक है।

6. **निष्कर्ष**– पेरिस करार के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन के लिए तथा आईएनडीसी में रखे गए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अधिक वित्त साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसी प्रकार संपोषणीय विकास उददेश्यों तथा लक्ष्यों को हासिल करने हेतु भी अत्याधिक वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी प्रयास करना आवश्यक है। भारत लंबे समय से सतत् विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके मुख्य बिन्दुओं को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल कर रहा है।

सन्दर्भ

1. यूपीयूईए इकोनॉमिक्स जर्नल, खण्ड–6, उत्तर प्रदेश–उत्तरांचल इकोनॉमिक एसोसिएशन, वाराणसी।
2. श्रीवास्तव, पी0 सी0(2014) वैश्विक तापन, अनुसंधान विज्ञान शोध पत्रिका, खण्ड–2, अंक–1, मु0पृ0 232–233।
3. तिवारी, ए0 के0(2015) वैश्विक तपन की बढ़ती गर्माहट, अनुसंधान विज्ञान शोध पत्रिका, खण्ड–3, अंक–1, मु0पृ0 203–204।
4. पेरिस एग्रीमेन्ट–विकिपीडिया 25.08.2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Agreement
5. कौशिक, ए0 एवं कौशिक, सी0 पी0(2009) पर्सपेक्टिव्स इन एनवायरमेन्टल स्टडीज, न्यू एज इनटरनेशनल प्रा0 लि0, नई दिल्ली।